राजस्व विभाग की नाक के नीचे बिका शासकीय भू-खण्ड

शहडोल में सरकारी जमीन की मची है लूट

पटवारी की मौन सहमति पर उठे सवाल

शहडोल।

जिला मुख्यालय के मुहाने पर बसे कल्याणपुर में इन दिनों भू-माफियाओं और राजस्व विभाग के रसूखदार गठजोड़ ने सरकारी संपत्तियों को अपनी जागीर समझकर लूटना शुरू कर दिया है। सरकारी जमीन, जिसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, आज उसे ऑफ-रिकॉर्ड चंद रुपयों की खातिर भू-माफियाओं के हवाले किया जा रहा है। ताज़ा मामला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के ठीक सामने का है, जहां एक बेशकीमती शासकीय भू-खण्ड का सौदा कथित तौर पर 4 से 5 लाख रुपये में कर दिया गया और अब वहां प्रशासनिक शह पर बेधडक़ निर्माण कार्य जारी है।

जिम्मेदारों की जेब गर्म, सरकारी जमीन नर्म

कल्याणपुर में चल रहा यह खेल कोई नया नहीं है, लेकिन अब इसने बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया है। सूत्रों की मानें तो राजस्व अमले के कुछ जिम्मेदारों ने पर्दे के पीछे रहकर इस पूरी डील को अंजाम दिया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सरकारी जमीन की रक्षा कौन करेगा? जिला मुख्यालय से सटे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में राजस्व अमले की संदिग्ध भूमिका ने पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

पटवारी प्रद्युमन पयासी को सब खबर

हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पटवारी प्रद्युमन पयासी को इस अवैध कब्जे और निर्माण की पूरी जानकारी है। इसके बावजूद, मौके पर कोई ठोस कार्रवाई न होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या पटवारी की यह चुप्पी किसी बड़े आशीर्वाद का परिणाम है? आखिर क्यों एक सरकारी कर्मचारी अपनी आंखों के सामने सरकारी संपत्ति को लुटते देख हाथ पर हाथ धरे बैठा है? जनता अब सीधे पूछ रही है कि क्या पटवारी साहब की निष्ठा सरकारी नियमों के प्रति है या फिर उन भू-माफियाओं के प्रति जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है?

फल-फूल रहा माफिया

यह समस्या सिर्फ कल्याणपुर तक सीमित नहीं है। जिला मुख्यालय के चारों ओर और कस्बाई क्षेत्रों में राजस्व विभाग के जिम्मेदारों ने सरकारी भूमि को अपनी कमाई का एटीएम बना लिया है। भू-माफिया जमीन चिह्नित करते हैं और राजस्व अमला कागजों में हेरफेर या मौन समर्थन देकर कब्जा पक्का करा देता है। कल्याणपुर में आज भी दर्जनों ऐसे आलीशान भवन खड़े हैं, जिनकी नींव सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के साथ रखी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कभी उन पर बुलडोजर चलाने की जहमत नहीं उठाई।

प्रशासनिक लकवा या भ्रष्टाचार का जाल

शासकीय भूमि पर मंडराता यह खतरा जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बदनुमा दाग है। जब जिला मुख्यालय के नाक के नीचे सरकारी दफ्तर के सामने जमीन बिक रही हो, तो दूरदराज के क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। समय रहते यदि इस लैंड जिहाद और राजस्व विभाग के भ्रष्ट गठजोड़ पर प्रहार नहीं किया गया, तो आने वाले समय में जिले में सार्वजनिक कार्यों के लिए एक इंच जमीन भी शेष नहीं बचेगी।

कलेक्टर से न्याय की दरकार

अब जिले के जागरूक नागरिकों की नजरें कलेक्टर पर टिकी हैं। क्या वे कल्याणपुर के इस जमीन घोटाले की निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्या पटवारी और उन राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने सरकारी जमीन का सौदा होने दिया? जनता की मांग है कि कल्याणपुर में हुए इस अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि सरकारी जमीन की लूट का यह धंधा हमेशा के लिए बंद हो सके।

खबर संक्षेप

कुबरा में कुएं के भीतर मिला गर्भवती का शव

शहडोल। जिले के जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कुबरा में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक 4 माह की गर्भवती नवविवाहिता का शव घर के सामने स्थित कुएं में उतराता मिला। महज 6 महीने पहले ब्याही गई 21 वर्षीय दीपा साहू (पति रवि साहू) की इस संदिग्ध मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के वक्त मृतका घर पर अकेली थी और परिवार के लोग मजदूरी पर गए हुए थे। शाम को जब पति रवि घर लौटा और पत्नी गायब मिली, तो खोजबीन शुरू हुई। कुएं के मुहाने पर पड़ी दीपा की चप्पल देखकर पति का माथा ठनका। ग्रामीणों ने कुएं में कांटा डाला, तो शव फंसा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कुएं से बाहर निकलवाया। मृतका का मायका मोहानी गांव में है। तीन बहनों में सबसे बड़ी दीपा के माता-पिता पेट पालने के लिए पुणे में मजदूरी करते हैं। उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तब तक लाश को मर्चुरी में सुरक्षित रखवाया गया है। अंधेरे कुएं में समाई इस जिंदगी की हकीकत क्या है? यह महकज एक हादसा है या इसके पीछे कोई खौफनाक साजिश? पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है, लेकिन इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं आम हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मायके पक्ष के बयानों के बाद ही इस रहस्यमयी मौत का असली सच सामने आ सकेगा।

अभिनय के साथ अंक ज्योतिष और वास्तु में संजय श्रीवास्तव ने गाड़े सफलता के झंडे

शहडोल। प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती और जब इरादे फौलादी हों, तो छोटे शहरों से निकले हुनर भी मायानगरी मुंबई की चकाचौंध में अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही शहडोल के गांधी चौक की गलियों से निकले संजय श्रीवास्तव ने कर दिखाया है, उन्होंने न केवल अभिनय की दुनिया में लोहा मनवाया है, बल्कि अपनी गहरी दूरदर्शिता के चलते अंक ज्योतिष (न्यूमरोलॉजी) और वास्तु परामर्श के क्षेत्र में भी देश-विदेश में एक विशिष्ट और सम्मानित स्थान हासिल किया है। आज सात समंदर पार तक उनके ज्ञान का डंका बज रहा है। संजय श्रीवास्तव के इस चमत्कारी सफर की शुरुआत असम के गोलपाड़ा में उनके सेवा काल के दौरान हुई थी। शुरुआत में जो अध्ययन महज एक शौक था, उसे वर्ष 2015 में उन्होंने एक प्रोफेशन का रूप दिया। अपनी अनूठी और सटीक गणनाओं के दम पर आज उनके पास 5000 से अधिक संतुष्ट क्लाइंट्स का एक बड़ा कारवां है, जिसमें 200 से ज्यादा विदेशी नागरिक शामिल हैं। बाजार में बैठे अन्य ज्योतिषियों और वास्तुविदों की तुलना में संजय श्रीवास्तव की कार्यशैली बेहद व्यावहारिक और जनहितैषी है, वे परामर्श के बाद अपने स्वयं के शोध से तैयार एक विशेष न्यूमरोलॉजी कार्ड देते हैं, जिसे जेब में रखने मात्र से सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। वे महंगे अनुष्ठानों के बजाय आम आदमी के बजट वाले सरल और घरेलू उपायों पर जोर देते हैं। जहां लोग वास्तु दोष के नाम पर लाखों के मकान तुड़वा देते हैं, वहीं संजय श्रीवास्तव बिना किसी तोड़-फोड़ के, केवल आंतरिक बदलावों से घर में सकारात्मकता ला देते हैं। एक अभिनेता, मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक गुरु के रूप में संजय श्रीवास्तव ने शहडोल का नाम वैश्विक पटल पर रोशन किया है। उनकी यह कामयाबी आज जिले के हर उस युवा के लिए बड़ी प्रेरणा है जो अपनी मेहनत के दम पर आसमान छूने का ख्वाब देखता है।

वैष्णव की फिसलन के सफल मंचन ने दर्शकों को किया आत्ममंथन के लिए प्रेरित

शहडोल। 11 दिवसीय नाट्य रंग महोत्सव शहडोल-2026 के आठवें दिन होटल शुभम पैलेस में हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध व्यंग्य रचना वैष्णव की फिसलन का सफल मंचन किया गया। प्रस्तुति का निर्देशन एवं संगीत परिकल्पना रोशनी प्रसाद मिश्र ने किया, जबकि एकल अभिनय शैली में सजल मिश्रा ने प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों का मन मोह लिया।

गांधी चौक पर एनएसयूआई ने फूंका चुनाव आयोग का पुतला

नटराजन का नामांकन रद्द होने पर भारी आक्रोश

शहडोल।

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन नियमों को ताक पर रखकर निरस्त किए जाने के खिलाफ जिला मुख्यालय में सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग पर बेईमानी और पक्षपात का संगीन आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने शहडोल की सडक़ों पर उतरकर जोरदार हुंकार भरी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय अवस्थी के मार्गदर्शन एवं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी के नेतृत्व में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने स्थानीय गांधी चौक पर चुनाव आयोग का पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

पुतला दहन के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवस्थी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यसभा निर्वाचन प्रक्रिया में जिस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है, उसने देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्वायत्त संस्थाएं अब सत्ता के दबाव में काम कर रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।

एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक परंपराओं की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। षड्यंत्रपूर्वक विपक्ष की आवाज को दबाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसे देश का छात्र और युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं, युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष तिवारी ने कहा कि इस तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई से देश के युवाओं और आम नागरिकों में गहरा आक्रोश है।

प्रदर्शन के दौरान गांधी चौक लोकतंत्र की हत्या बंद करो और चुनाव आयोग होश में आओ जैसे गगनभेदी नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने दोटूक शब्दों में कहा कि यदि चुनाव आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया और पूरे मामले की पारदर्शी जांच नहीं कराई, तो यह आंदोलन उग्र रूप अख्तियार करेगा। इस बड़े राजनैतिक विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से नीरज द्विवेदी, अनुज मिश्रा, कुलदीप निगम, सबी खान बंटी, प्रीतम सोनी, अजीत सोनी, हीरालाल प्रजापति, सतनारायण साहू, प्रमोद जैन, रामनरेश तिवारी, आशीष त्रिपाठी सहित मान्या, ओम कृतेंद्र, हर्षित श्रीवास्तव, नावेद आलम, और दानिश रज़ा समेत युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

शिक्षक कांग्रेस ने पीएम के नाम खोला मोर्चा संशोधन की उठी मांग, सडक़ों पर उतरने की चेतावनी

शहडोल। दशकों तक देश की नई पीढ़ी का भविष्य संवारने वाले अनुभवी शिक्षकों के स्वाभिमान पर जब पात्रता परीक्षा की तलवार लटकी, तो शिक्षकों का सब्र जवाब दे गया। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन की स्पष्ट मांग है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नाम पर पुराने और अनुभवी शिक्षकों पर थोपी गई पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को तत्काल निरस्त किया जाए। शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कानून की पेचीदगियों पर प्रहार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां आरईटी एक्ट (2009) लागू होने से बहुत पहले राज्य सरकारों की नीतियों के तहत हुई थीं, लेकिन 2017 के संशोधन के बाद, पुराने शिक्षकों को भी परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह देश का ऐसा पहला कानून है जो बैकडेट (भूतलाक्षी) आधार पर लागू किया जा रहा है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सरेआम धज्जियां उड़ाना है। 20 वर्षों से अधिक समय तक शासकीय सेवा देने वाले शिक्षकों से इस उम्र में उच्च स्तरीय परीक्षा लेना उनके समर्पण और अनुभव का अपमान है। ज्ञापन में उल्लेख है कि इस अव्यावहारिक कानून की वजह से अकेले मध्य प्रदेश के करीब 50 लाख और देशभर के लाखों शिक्षकों का मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। शिक्षकों का सवाल है कि क्या 20 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद अब उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी प्रमाण-पत्र की जरूरत है? मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आरईटी एक्ट 2017 को पुनः संशोधित किया जाए और कानून लागू होने से पहले नियुक्त हो चुके सभी अनुभवी शिक्षकों को इस पात्रता परीक्षा के जाल से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान चांद सिंह पट्टावी संभागीय अध्यक्ष, अख्तर हुसैन अध्यक्ष, कमलेश मिश्रा और केदार मिश्रा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार नहीं किया गया, तो यह विरोध केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा।

गुजरात का मूर्ति चोर शहडोल में उड़ा रहा था बुलेट! अमलाई पुलिस ने दबोचा डायरेक्ट कनेक्शन गिरोह

गैराज की आड़ में चलता था पुर्जे बदलने का खूनी धंधा

शहडोल। भीड़भाड़ वाले इलाकों और शादी-पार्टियों से पलक झपकते ही मोटरसाइकिल पार करने वाले अंतर-राज्यीय गिरोह का अमलाई पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज भंडाफोड़ किया है, जिसके तार सीधे गुजरात की बड़ी चोरियों से जुड़ रहे हैं। बिना चाबी के, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन देकर मिनटों में लग्जरी गाडिय़ां उड़ाने वाले इस शातिर गिरोह के दो गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि पकड़ा गया मुख्य शातिर अमन तिवारी पहले गुजरात के एक मंदिर से बेशकीमती मूर्ति चोरी करने के संगीन मामले में भी जेल की हवा खा चुका है।

मैकेनिक निकला मास्टरमाइंड- पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमन तिवारी और उसके साथी दीपू सिंह को दबोचकर 7 चोरी की बाइक बरामद की हैं, लेकिन इस पूरे सिंडिकेट का सबसे खौफनाक चेहरा अभी फरार है। गिरोह का मास्टरमाइंड मंगेश सिंह और उसका साथी नमन केवट पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। मास्टरमाइंड मंगेश बुढार में बाइक रिपेयरिंग का गैराज चलाता है। चोरी की गाडिय़ों को सीधे इसी गैराज के बूचडख़ाने में लाया जाता था, जहां उनके कीमती पाट्र्स निकालकर दूसरी गाडिय़ों में फिट कर दिए जाते थे और उन्हें बाजार में मोटी रकम में खपाया जाता था।

3 महीने से मचा रखा था कोहराम- शातिरों की कार्यशैली इतनी हाईटेक थी कि वे ओपीएम कॉलोनी, बकहो और आसपास के शादी समारोहों के बाहर रेकी करते थे। जैसे ही कोई बिना लॉक की गाड़ी दिखती, अमन तकनीकी रूप से तार डायरेक्ट कर उसे स्टार्ट करता और दीपू के साथ रफूचक्कर हो जाता। पुलिस ने मंगेश के गैराज पर छापा मारकर 4 कटी हुई गाडिय़ां और अलग-अलग ठिकानों से बुलेट, यामाहा आर-15 व स्कूटी सहित 3 अन्य गाडिय़ां बरामद की हैं। थाना प्रभारी भूपेंद्रमाणि पांडेय के नेतृत्व में पुलिस की टीमें फरार गैराज संचालक और उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि मास्टरमाइंड के हत्थे चढऩे के बाद कई और बड़े चेहरों से नकाब उतरना तय है।

इनका कहना है...

बाइक चोरी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो की तलाश की जा रही है, वही 7 चोरी की बाइक जप्त कर कार्यवाही की गई है। अभी भी कार्यवाही जारी है।

भूपेंद्र मणि पाण्डेय
थाना प्रभारी, अमलाई

उप पंजीयक सचिन जैन की वापसी पर भडक़ा आक्रोश

अभिभाषक संघ ने कलेक्टर के सामने खोला मोर्चा

शहडोल।

सरकारी दफ्तरों में जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार और दबंगई के खिलाफ अब सोहागपुर राजस्व अभिभाषक संघ ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। मामला उप पंजीयक कार्यालय सोहागपुर में सहायक वर्ग-2 सचिन जैन की पुनः पदस्थापना से जुड़ा है, जिसका वकीलों और आमजन ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। संघ के अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारियों ने कलेक्टर को शिकायती ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस विवादित कर्मचारी को दोबारा जॉइन कराया गया, तो आंदोलन उग्र होगा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सचिन जैन पूर्व में भी उप पंजीयक के प्रभार में रह चुका है और उसका वह कार्यकाल जनता के लिए किसी मानसिक प्रताडऩा से कम नहीं था। अभिभाषक संघ का कहना है कि रजिस्ट्री कराने आने वाले आम नागरिकों से अनाप-शनाप रुपयों की मांग की जाती थी। दस्तावेजों में जानबूझकर खामियां निकाली जाती थीं और मनमुताबिक वसूली न होने पर रजिस्ट्री को होल्ड पर डाल दिया जाता था। विरोध करने वाले नागरिकों और अधिवक्ताओं के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करना इस कर्मचारी की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका था। शिकायत में सबसे चौंकाने वाला खुलासा सचिन जैन की कथित दबंगई को लेकर किया गया है। संघ के अनुसार, वह खुलेआम धमकी देते थे कि भोपाल और जबलपुर के बड़े अधिकारियों का उन्हें वरदहस्त प्राप्त है, इसलिए इस जिले या संभाग का कोई भी अधिकारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह घमंड इस कदर हावी था कि वह यहां की जनता को अपनी चारागाह समझकर अवैध वसूली में लिप्त रहता था।अभिभाषक संघ ने सवाल उठाया है कि जब सचिन जैन को विवादों के कारण यहां से हटाया गया था, तो अब वह स्वयं के व्यय पर वापस सोहागपुर ही क्यों आना चाहते है? क्या यहां फिर से भ्रष्टाचार का खेल खेलने की तैयारी है, संघ ने मांग की है कि किसी जिम्मेदार और स्वच्छ छवि वाले वरिष्ठ उप पंजीयक की नियुक्ति की जाए, न कि सचिन जैन जैसे भ्रष्ट और विवादित कर्मचारी को फिर से महत्वपूर्ण पद का प्रभार सौंपा जाए। संघ के अध्यक्ष नवदुर्गेश मिश्रा, महासचिव प्रत्यूष रजक और अन्य पदाधिकारियों ने दोटूक शब्दों में कहा है कि सोहागपुर की भोली-भाली जनता को अब और लूटने नहीं दिया जाएगा।

आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत

शहडोल। बिजली विभाग की संवेदनहीनता और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखने की जिद ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली है। सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आकाशवाणी के पास बिजली सुधारने गया आउटसोर्स कर्मचारी कुंदन सिंह निवासी मलचुआ सिस्टम के करंट की भेंट चढ़ गया। क्रिस्टा कंपनी के इस कर्मचारी को बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के मौत के मुंह में धकेल दिया गया, जहां करंट की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो कुंदन लाइन पर काम कर रहा था, तभी अचानक हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। सवाल यह उठता है कि जब कर्मचारी खंभे पर था, तो बिजली चालू किसने की, क्या विभाग और आउटसोर्स कंपनी के बीच तालमेल सिर्फ कागजों तक सीमित है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्रिस्टा कंपनी और एमपीईबी के अधिकारी चंद रुपयों की बचत के लिए गरीब कर्मचारियों को बिना दस्ताने, बेल्ट और हेलमेट के यमराज के हवाले कर देते हैं। हादसे के बाद विभाग के आला अधिकारी अपनी खाल बचाने के लिए चुप्पी साधे बैठे हैं, वहीं मृतक के घर में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे न्याय की भीख मांग रहे हैं। जनता अब सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर इस कत्ल का जिम्मेदार कौन? क्या विभाग के लापरवाह इंजीनियरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा या हर बार की तरह मामले को लीपापोती कर दबा दिया जाएगा, प्रशासन को अब जवाब देना ही होगा, क्योंकि यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही से की गई हत्या है।

इनका कहना है...

आउटसोर्स कर्मचारी की करंट लगने से मौत की जानकारी मिली है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कर्मचारी किसके निर्देश पर और किस स्थान पर बिजली सुधारने गया था, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विनोद कुमार
सहायक अभियंता एमपीईबी, शहडोल

खबर संक्षेप

जिला प्रभारी मंत्री का भ्रमण कार्यक्रम

उमरिया। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान एक दिवसीय भ्रमण पर 17 जून को उमरिया आएंगे। श्री चौहान 17 जून बांधवगढ़ से उमरिया सर्किट हॉउस के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रातः 11 बजे माध्यमिक विद्यालय अमिलिहा विकास खंड पाली में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल होंगे। दोपहर 12.30बजे गायत्री मंदिर के सामने पाली में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल होंगे। दोपहर 1.30 बजे ग्राम भिम्माडोंगरी में नल जल योजना का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 3 बजे जल हली धाम ग्राम सेहराटोला जरहा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होंगे। सायं 4 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे।

15 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

उमरिया। मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक की अवधि को मत्स्य प्रजनन काल होने से बंद ऋतु घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन के ज्ञापन क्रमांक अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबध किसी नदी से नहीं है, और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अन्तर्गत नही लाया गया है, को छोडकर समस्त नदियों एवं जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या (पांच हजार) का जुर्माना या दोनों रो दंण्डित किये जाने का प्रावधान है। उन्होने कहा है कि अधिसूचना के माध्यम से कहा गया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार मत्स्याखेट कय-दिव्य परिवहन न करे, और न ही ऐसे कार्य में किसी अन्य को सहयोग दें अन्यथा कि स्थिति में उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

सर्प प्रहरी नवीन महाडिक क्षेत्र के लिए हैं वरदान

चचाई। ऊर्जा नगरी चचाई के एक साहसी युवा नवीन महाडिक चचाई थाना क्षेत्र में हर मौसम में जहरीले सांप एवं अन्य जीव जंतुओं जिनका विचरण अक्सर लोगों के घर व आंगन में देखने को मिलता है जो लोगों के जीवन को संकट में डाल देते हैं ऐसे समय में लोग इस युवा नवीन महाडिक को याद करते हैं यह कार्य चचाई, केल्हौरी, विवेक नगर, खुटवा, देवरी, परसवार, बकेली, मेडियारास, सकोला आदि आसपास के गांव के लोग फोन करके बुलाते हैं जहां तत्काल वे अपने वाहन से पहुंचकर जहरीले जीवो को जानजोखिम में डालकर पकडते हैं और लोगों की मदद करते हैं अक्सर बरसात के दिनों में जहरीले जीव लोगों के घरों में घुसते हैं ऐसे समय में उनकी मदद के साथ-साथ यह युवा उन्हें इनसे बचने की समझाइस भी देते हैं जहरीले जीवों को पकड़ने के बाद उन्हें सुरक्षित जंगलों में ले जाकर छोड़ने का काम भी अपने स्वयं के खर्चे से करते हैं ऐसे सर्पप्रहरी को जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की मदद नहीं दी जाती जो आम जनता की समझ से परे हैं जानकारी के अनुसार एक वर्ष पूर्व नवीन महाडिक के बड़े भाई मनोज महाडिक उर्फ बंटी द्वारा पूरे क्षेत्र में यही समाज सेवा का काम करते थे किंतु उनके देहांत हो जाने के बाद यह कार्य उनके छोटे भाई नवीन ने अपना लिया यह ऐसा युवा है जो कभी रुकता नहीं थकता नहीं इन्होंने थाना क्षेत्र के ग्राम वासियों को मदद हेतु अपने मोबाइल नंबर 7000437824 के माध्यम से किसी भी समय मदद करने की बात कही है।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी माला पंचायत

कागजों में नरेगा और जमीन पर मशीन का खेल!

मजदूरों के हक पर चला जेसीबी का पंजा

मानपुर। जनपद पंचायत मानपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माला में भ्रष्टाचार का एक ऐसा नग्न नाच देखने को मिल रहा है, जहाँ शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं और नियम-कायदे पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों की जेब भरने का जरिया बन गए हैं। जमुनारा हनुमान मंदिर के नीचे बन रहे तालाब निर्माण में सरेआम नरेगा के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मजदूरों के हाथों से निवाला छीनकर सरपंच, सचिव और इंजीनियर की मशीनी जुगलबंदी ने ग्रामीणों को पलायन की आग में झोंक दिया है।

मशीन से भरा जा रहा अपना घर

शासन की मंशा है कि गांव के गरीब मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, लेकिन ग्राम पंचायत माला में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। जमुनारा हनुमान मंदिर के नीचे तालाब निर्माण में मजदूरों की जगह जेसीबी और ट्रैक्टरों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। आलम यह है कि गांव के गरीब मजदूर काम की तलाश में भटक रहे हैं और विवश होकर अपने भरण-पोषण के लिए गढ़ाकोटा जैसे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो भला मजदूरों की सुध कौन लेगा?

तीन साल बाद जागी कुंभकर्णी नींद

हैरानी की बात यह है कि जिस तालाब की स्वीकृति तीन-चार वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी सुध पंचायत के कर्णधारों को नरेगा बंद होने की आहट के बीच अब आई है। सवाल उठता है कि आखिर तीन वर्षों तक यह फाइल किन अलमारियों में धूल फांक रही थी? स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जनपद के आला अधिकारियों, सरपंच, सचिव और इंजीनियर की मिलीभगत से इस निर्माण कार्य को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया गया है। शासन को ठेंगा दिखाते हुए यह गिरोह अपनी दबंगई के दम पर भ्रष्टाचार की नई इबारत लिख रहा है।

जंगल की जमीन और सीमा का उल्लंघन

यह पूरा निर्माण कार्य न केवल आर्थिक भ्रष्टाचार, बल्कि प्रशासनिक अनियमितता का भी जीता-जागता उदाहरण है। बताया जा रहा है कि जमुनारा मंदिर के नीचे हो रहा यह निर्माण कार्य वन विभाग की सीमा के भीतर है। चन्द रुपयों के लालच में नियमों को ताक पर रखकर जंगल की जमीन पर जेसीबी चलाई जा रही है। हद तो तब हो गई जब माला पंचायत ने सरमनिया और जमुनारा के नाम पर स्वीकृत 24 लाख रुपयों (12-12 लाख प्रत्येक) का उपयोग दूसरी पंचायत की सीमा में कर दिया। सरमनिया का तालाब ग्राम पंचायत पतौर की सीमा (केवट मोहल्ला) में बनवा दिया गया, जो कि सरकारी गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है। क्या पतौर पंचायत के पास बजट नहीं था, या माला पंचायत के रसूखदारों को अपनी मनमानी के लिए कोई सरहद नहीं दिखती?

सीसी रोड में भी कमीशनखोरी का खेल

माला पंचायत में भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ तालाब तक सीमित नहीं हैं। यहां बनी सीसी रोड भ्रष्टाचार का जीता-जागता प्रमाण पेश कर रही हैं। नियमानुसार, सीसी रोड बनने के तुरंत बाद उसके दोनों ओर मिट्टी की पटरी भरना अनिवार्य है ताकि बरसात में कटाव न हो और सडक़ सुरक्षित रहे, लेकिन सरपंच-सचिव की दबंगई ऐसी कि आज दिनांक तक पटरी का भराव नहीं किया गया। यह लापरवाही आने वाले समय में सरकारी पैसे से बनी सडक़ के अस्तित्व को मिटाने के लिए काफी है।

कलेक्टर और सीईओ से न्याय की आस

ग्राम पंचायत माला की इस अंधेर नगरी से जनता अब त्रस्त हो चुकी है। ग्रामीणों ने कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय और जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ओहरिया से मांग की है कि माला पंचायत में हुए और हो रहे सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए। मजदूरों के हक पर डाका डालने वाले मशीनी उपयोग की सघन जांच कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाए। सीमा उल्लंघन कर बनाई गई परिसंपत्तियों और गायब पटरी भराव के नाम पर डकारे गए पैसों की रिकवरी की जाए।

खेल से होता है मानसिक एवं बौद्धिक विकासः अनुजा पटेल

उमरिया में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

उमरिया। जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम उमरिया में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल, कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न संभागों से आई टीमों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल ने कहा कि उमरिया जिले में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होना जिले के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। खेल न केवल शारीरिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि मानसिक मजबूती, अनुशासन एवं नेतृत्व क्षमता का भी विकास करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल में हार-जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना और उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है तथा सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।

कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने खिलाड़ियों से अनुशासन एवं खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिले में आए सभी खिलाड़ियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा व्यक्त की।

इस अवसर पर राकेश शर्मा ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना के साथ मैदान में उतरने का संदेश दिया। जिला शिक्षा अधिकारी आर.एस. मरावी ने बताया कि प्रतियोगिता में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम तथा जनजातीय कार्य विभाग की टीमें भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगी।कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल एवं कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय द्वारा खेल ध्वज फहराकर किया गया। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर खेल ध्वज एवं मुख्य अतिथि को सलामी दी। इस दौरान खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई गई तथा टीमों के साथ आए कोचों को टी-शर्ट वितरित की गई। समारोह में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ), जिला शिक्षा अधिकारी सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं सीईओ ने 149 आवेदकों की सुनी समस्यां

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं सी ई ओ जिला पंचायत अभय सिंह ने जिले के दूर दराज से आये 149 आवेदकों की समस्या सुनी एवं आवेदनों के निराकरण के लिए आवेदन संबंधित विभाग की ओर प्रेषित किया।

जनसुनवाई में विजय कुमार रजक ग्राम कछरवार ने मेड़ बंधान नष्ट करने पर देवशरण पर कानूनी कार्यवाही किये जाने, मनीषा सिंह नौगवा ने पुस्तैनी भूमि से कब्जा हटाने, मनीलाल बैगा ग्राम भरौला ने आराजी का पट्टा दिलाने, बारेलाल प्रजापति मानपुर ने नक्शा तरमीम , सीमांकन कराने, बुद्धसेन यादव बड़ागांव ने पी एम आवास दिलाने, पंचम सिंह ग्राम दुलहरी ने सिंचाई विभाग से बांध का मुआवजा दिलाने, रानी बाई चंदवार ने मकान की मरम्मत हेतु सहायता राशि दिलाने, मिही लाल कोल ग्राम खुटार ने रास्ता दिलाने सम्बधी आवेदन दिया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता , संयुक्त कलेक्टर अमित सिंह, एस डी एम बांधवगढ़ अम्बिकेश प्रताप सिंह सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

कोतमा पुलिस की कार्यवाही अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त

कोतमा। विशेष अभियान के तहत थाना कोतमा द्वारा अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। 14 जुन को थाना प्रभारी कोतमा को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति केवाई नदी से बिना नंबर के नीले रंग के स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध रेत लोड कर निगवानी की ओर ले जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना कोतमा पुलिस टीम ने विशुन टोला निगवानी के पास घेराबंदी की। जिस पर एक नीले रंग का बिना नंबर का स्वराज ट्रैक्टर मय रेत भरी ट्राली के चालक विवेक तिवारी पिता गणेश तिवारी उम्र 29 वर्ष निवासी निगवानी के कब्जे से बिना रॉयल्टी के जप्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रत्नांबर शुक्ल के साथ प्रधान आरक्षक रामखेलावन यादव, आरक्षक 301 महेश साहू एवं चालक आरक्षक अनिल मरावी की अहम भूमिका रही। अनूपपुर पुलिस द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है।

उप पंजीयन कार्यालय में पंजीयक नदारत, कार्यालय में लटक रहा ताला

कोतमा। जमीनों की रजिस्ट्री के लिए किसान व आम लोगों को कोतमा तहसील उपपंजीयक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अव्यवस्था का आलम यह है कि इस भीषण गर्मी में 40-50 किमी दूर से कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को समय पर रजिस्ट्री नहीं होने से बैरंग लौटना पड़ रहा है। अधिकारियों के इस रवैये से किसानों में आक्रोश है। ऐसी स्थिति में कार्यालय पहुंच रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की शिकायत पर सुबह 10.30 बजे हरिभूमि की टीम उपपंजीयक कार्यालय पहुंची, जहां रजिस्ट्री के लिए 10 से अधिक पक्षकार कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी नदारद मिले। इस संबंध में किसानों से जानकारी लेने पर बताया कि वर्षों से यही हालात बने हुए हैं। मार्च माह मे कोतमा उपपंजीयक कार्यालय मे विजय जाट की शासन द्वारा उपपंजीयक के पद पर पदस्थापना की गई थी लेकिन अप्रैल माह से यह नदारत है कार्यालय मे ताला लटक रहा है।एक माह जब बैठे तो वह भी बिजोलियों के कार्य से ही फुर्सत नहीं होते। आलम यह है कि कोतमा मे स्थित लगभग कार्यालय प्रभार के भरोसे संचालित हो रहे हैं जबकि इस क्षेत्र से विधायक दिलीप जायसवाल संभाग के इकलौते मंत्री हैं और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हाल बेहाल है। जिसके कारण आम जनमानस परेशान नजर आ रहा है। पूर्व मे मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि शहडोल संभाग में कोई भी कार्यालय प्रभार के भरोसे संचालित नहीं होगे उसके बाद भी हाल बेहाल है।कोतमा तहसील मुख्यालय में स्थित उपपंजीयक कार्यालय बीते 1 वर्ष से बंद पड़ा था, जिससे आम जनता, खासकर जमीन के खरीददार और विक्रेताओं के साथ ही वसीयत नामा बनवाने को लेकर हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मार्च माह मे उपपंजीयक की पदस्थापना जरूर की गई लेकिन वह नदारत है कार्यालय बंद होने के कारण न तो रजिस्ट्री हो पा रही है और ना ही संबंधित दस्तावेजों की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। सैकड़ों फाइलें अटकी हुई हैं और आमजन को 40 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय मे स्थित अनूपपुर कार्यालय का रुख करना पड़ रहा है। कोतमा स्थिति उपपंजीयक सुनील विश्वकर्मा का स्थानांतरण बीते वर्ष शहडोल के लिए हो गया था, उनकी जगह बिजय जाट की पदस्थापना की गई है। लेकिन वह भी नदारत रहते हैं यह लापरवाही न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर चिंता का विषय है, बल्कि आम नागरिकों के हितों पर भी सीधा आघात है। भूमि खरीदी-बिक्री, ऋण दस्तावेज, वसीयत नामांतरण जैसे जरूरी कार्य ठप्प हो गए हैं। तहसील क्षेत्र के अनेक किसान, व्यापारी और नागरिक जो वर्षों की पूंजी से जमीन क्रय करना चाहते थे, अब रजिस्ट्री न होने से असमंजस में हैं। उप पंजीयक तहसील कोतमा के हितग्राहियों को 40 किलोमीटर दूर अनुपपुर जाना पड़ रहा। कोतमा क्षेत्र के नागरिकों को अब जमीन से जुड़ा कोई भी दस्तावेज पंजीकृत कराने के लिए अनूपपुर स्थित उपपंजीयक कार्यालय जाना पड़ रहा है, जो कि न सिर्फ समयसाध्य है बल्कि आर्थिक रूप से भी बोझिल है। अनेक ग्रामीणों ने बताया कि रोज़ाना अनूपपुर जाकर फॉर्म भरना, पर्ची लेना और लाइन में लगना बेहद कठिन और अपमानजनक अनुभव है। भूमि पंजीयन कार्य के ठप्प होने से राजस्व संग्रह और शासकीय कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों के ज़रूरी सौदे अटक गए हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ बाधित हो रही हैं।स्थानीय नागरिकों और अधिवक्ताओं ने इस गंभीर स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे वादे करती है वहीं जमीनी हकीकत यह है कि एक तहसील का उप पंजीयन कार्यालय ही लगभग ढाई माह से नियमित संचालित नहीं हो रहा है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों अधिवक्ताओं एवं नागरिकों ने जिला प्रशासन और राज्य शासन से कोतमा उप पंजीयन कार्यालय में तत्काल नियमित रूप से पंजीयन की बैठने की व्यवस्था की मांग की है ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।

तेजी से फल-फूल रहा अवैध प्लाटिंग का कारोबार

कालोनी में माकान बनने के बाद नही दे रहे सुविधा, रहवासी परेशान

कोतमा। नगर सहित गाँवों की कीमती जमीनों पर भू माफियाओं की नजर गड़ी हुई है। नगर में अवैध प्लाटिंग कर जमीन की खरीद फरोख्त का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। लोग खुद के आशियाने की उम्मीद में नियमों की अनदेखी कर जमीन खरीद रहे हैं। अवैध प्लाटिंग के मामले पर प्रशासन की ओर से ठोस कार्यवाही न किये जाने के कारण बिचौलिए लोगों की जीवन भर की कमाई को खुले आम लूट रहे हैं। नगर की आबादी दिनो दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग अब खुद के आशियाने के लिए जमीन की खाक छान रहे हैं। भू माफिया इसका नाजायज फायदा उठाते हुए पहले तो गांव सहित शहर की जमीन की औने पौने दाम पर खरीद फरोख्त करते हैं। इसके बाद किसानों से खरीदी गई कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जाती है और उसे बेच दिया जाता है। मोटी कमाई के लिए दलाल सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नगर में जमीन की खरीदी बिक्री हर दिन हो रही है। नगर के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 के किनारे कृषि भूमि को अवैध प्लाटिंग कर बेजा जा रहा है। पिछले कई वर्ष से यह सिलसिला जारी है। नगर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से कृषि भूमि खरीदी जाती है और बाद में भू माफिया इसे प्लाटिंग कर बेच देते हैं। जबकि प्लाटिंग और कॉलोनी संबंधी कार्य के लिए कॉलोनाइजर के पास प्लाटिंग की खरीदी बिक्री का लाइसेंस होना अनिवार्य होता है। ग्रामीण इलाकों के किसानों की कृषि भूमि को ज्यादा पैसे देकर खरीद ली जाती है। भूमि की खरीदी के बाद अवैध प्लाटिंग किया जाता है और उसे बेचा जाता है। औने-पौने दाम में खरीदे गए भूमि को कॉलोनी बनाए जाने के नाम पर बड़ी कीमत में बेचा जाता है। नियमों को ताक पर रखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में मुख्य मार्ग के अलावा एनएच बायपास के दोनों तरफ सहित नगर के कई वार्डों मे लगातार कालोनियां विकसित हो रही है। अवैध प्लाटिंग का धंधा जोर-शोर से चल रहा है। प्रशासन की मौन स्वीकृति के चलते भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ताल तलैया में भी आशियाने बसाऐ जा रहे हैं। नगर के अनेक तालाब तलैया भू माफियाओं की भेंट चढ़ गए। जिसका खामियाजा नगर वासियों को गंभीर जल संकट के दौर से गुजर कर चुकाना पड़ सकता है इसके बावजूद भी लगातार ताल तलैया को जमींदोज करने का कार्य बदस्तूर जारी है।

नगर के जमीन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण बिचौलियों के जरिए जमीन की खरीदी बिक्री होना है। यदि जमीन के लिए सीधे मालिक व ग्राहक के बीच सौदा होता है तो कमीशन का खेल ही नहीं हो पाएगा। ऐसे में जमीन सस्ते दाम में उपलब्ध हो सकेगी। शहरी क्षेत्र में ऐसे कई कालोनाईजर्स की भरमार है जो पैसे के बलबूते पर औने-पौने दामों में जमीन खरीदी कर अवैध प्लाटिंग कर बेच देते हैं। बावजूद इसके जमीन के इस गोरखधंधे को बंद कराने में प्रशासन ने अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। अवैध प्लाटिंग के जरिए हर वर्ष लाखों रुपए की राजस्व चोरी की जाती है। अवैध प्लाटिंग के जरिए कृषि भूमि को रहवासी क्षेत्र के लिए बेच दिया जाता है। वर्तमान में चल रहे अवैध प्लाटिंग करने वाले अब समूहों में कार्य करने लग गए हैं, जिससे राजस्व को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। पूर्व मे नगर पालिका राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में सड़क के किनारे अवैध प्लाटिंग को धराशाई कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से अबैध प्लाटिंग का कार्य भू माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से शुरू कर दिया गया है। खुलेआम बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के कई वार्डों में जमीन मालिकों के द्वारा प्लाटिंग का जमीन को बेच तो दिया गया और जमीन की बिक्री करते समय उनसे यह कहा गया था कि सड़क नाली एवं बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी लेकिन वर्तमान में कई ऐसी कालोनियां है जहां लोग मकान बनाकर रहने तो लगे हैं लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया गया जिसके कारण सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है पूरे कॉलोनी में कीचड़ ही कीचड़ रहता है तेज बारिश होने पर वह कॉलोनी तालाब के रूप में तब्दील हो जाती है नाली सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण लोग परेशानी से जूझते नजर आते हैं और बाद में नगर पालिका प्रशासन को कोसते हैं कि नगर पालिका के द्वारा सड़क नाली नही बनवाया जा रहा है ऐसे कॉलोनी के लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अवैध निर्माण मामले को काफी गंभीरता से लिया था। उन्होंने इस मामले में कड़े प्रावधान किए हैं जिसके अनुसार अवैध प्लाटिंग करने वाले भू माफियाओं पर रासुका लगाई जाएगी। कार्यवाही सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहेगी जिस इलाके में अवैध कॉलोनी बनी है या बनेगी वहां के राजस्व अधिकारियों पर भी सीधे कड़ी कार्यवाही होगी। जानकारी मिली है कि माफियाओं की पुरानी और नई हैसियत का आकलन किया जाएगा। निर्माण को जमीन दोज करने का कार्य तो पूर्व से ही शुरू कर दिया गया है इसे भी कड़ाई से लागू किया जाएगा। बताया गया कि भू माफियाओं की गोपनीय सूची भी तैयार की जाएगी ताकि उन पर कार्यवाही करने में सहूलियत हो सके।

खबर संक्षेप

बिजुरी पुलिस की जुआ फड़ पर बड़ी कार्रवाई

बिजुरी। जिले में अवैध गतिविधियों और जुआ-सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजुरी पुलिस को एक और सफलता मिली है। 13 जून को मुखबिर की सूचना पर बिजुरी पुलिस टीम ने डबल स्टोरी माइंस कॉलोनी में कटहल के पेड़ के नीचे चल रहे जुआ फड़ पर अचानक दबिश दी। मौके से पुलिस ने ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए 03 आरोपियों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में अरुण कुमार पाटकर 27 वर्ष पिता लल्लू प्रसाद पाटकर, अमर पनिका' 29 वर्ष पिता स्व. मोहरसाय पनिका, बबलू कोल 19 वर्ष पिता गोरेलाल कोल, सभी निवासी डबल स्टोरी माइंस कॉलोनी, थाना बिजुरी। पुलिस ने आरोपियों के पास और फड़ से कुल 1,760 नकद तथा 52 ताश के पत्ते जब्त किए हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ थाना बिजुरी में अपराध क्रमांक 209/2026, धारा 13 जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह, सहायक उप निरीक्षक कमलेश तिवारी, आरक्षक विश्वजीत मिश्रा एवं चालक आरक्षक करमजीत सिंह की उल्लेखनीय और सराहनीय भूमिका रही।

योग के साथ ग्रीष्म कालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन

कोतमा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर समारोह का समापन गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम कोतमा में किया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब, जिला एवं युवा कल्याण अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगनाथ मरकाम के निर्देशन में खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ 1 मई को हुआ था जिसमें खिलाड़ियों को खेलो सीखो आगे बढ़ाओ थीम पर दिया गया खेल समन्वयक मिथलेश सिंह नेताम ने बताया कि व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक जागरूकता पर भी कार्यक्रम किया गया। शिविर में एथलेटिक्स कबड्डी आत्म रक्षा प्रशिक्षण खेल की बारिकिया सीखकर अपने खेल कौशल मे सुधार किया गया। अतिथियों ने समापन अवसर पर कार्यक्रम में प्रमाण पत्र प्रदान कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। समापन कार्यक्रम में बादल राय जिला एथलेटिक्स संघ सचिव दीपक पांडे, साजन धीमान कराटे प्रशिक्षक दुर्गेश केवट उपस्थित रहे।

रीजनल वर्कशॉप की महिला कर्मचारी ने कलेक्टर, एसपी समेत कई विभागों से लगाई न्याय की गुहार, बोली— मेरे नाम पर चल रहा था क्वार्टर, मुझे खबर तक नहीं

पुनियाबाई के नाम क्वार्टर, कब्जा किसी और का! 12 साल तक वेतन से कटता रहा किराया, एसईसीएल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल

धनपुरी। एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र के बुढार ग्रुप में आवास आवंटन से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रीजनल वर्कशॉप धनपुरी में पदस्थ महिला कर्मचारी पुनियाबाई, पति स्वर्गीय सीताराम (टोकन क्रमांक 337) ने आरोप लगाया है कि उनके नाम पर वर्षों पहले एक क्वार्टर आवंटित कर दिया गया, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें कभी नहीं दी गई। हैरानी की बात यह है कि उक्त क्वार्टर का किराया लगभग 12 वर्षों तक उनके वेतन से कटता रहा, जबकि मकान पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा बना रहा।

पुनियाबाई के अनुसार वह प्रतिदिन बुढार से धनपुरी ड्यूटी करने आती हैं। लंबी दूरी और आवागमन की परेशानी को देखते हुए उन्होंने विभाग में क्वार्टर आवंटन के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि उनकी अशिक्षा का फायदा उठाकर संबंधित बाबू और कर्मचारियों ने उनके नाम से क्वार्टर आवंटित कर दिया, लेकिन उन्हें न तो आवंटन पत्र दिया गया और न ही किसी प्रकार की सूचना।

जब सच सामने आया तो उड़ गए होश

महिला कर्मचारी ने बताया कि जब उन्होंने हाल ही में आवास संबंधी जानकारी जुटाई, तब उन्हें पता चला कि उनके नाम पर वर्षों पहले ही क्वार्टर आवंटित हो चुका है। विभागीय रिकॉर्ड में मकान उनके नाम दर्ज था और उसका किराया भी नियमित रूप से उनके वेतन से काटा जा रहा था। यह जानकर वह स्तब्ध रह गईं कि जिस मकान का किराया वह भर रही थीं, उसका उपयोग कोई और कर रहा था।

क्वार्टर में वर्षों से रह रही थी दूसरी महिला

जानकारी के अनुसार संबंधित क्वार्टर में जमीला बेगम नामक महिला निवास कर रही थी। आरोप है कि बाद में मकान को तोड़कर नए सिरे से निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया। स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद मामला अधिकारियों तक पहुंचा और तब जाकर पुनियाबाई को अपने नाम पर आवंटित क्वार्टर की जानकारी मिली।

रिटायरमेंट के बाद बन सकता है बड़ा संकट

मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि विभागीय रिकॉर्ड में क्वार्टर पुनियाबाई के नाम दर्ज है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के समय यदि कंपनी को क्वार्टर हैंडओवर नहीं किया जाता, तो पूरी जवाबदेही उन्हीं पर आएगी। इसके अलावा क्वार्टर से जुड़ी किसी भी दुर्घटना, विवाद या कानूनी मामले में भी उनका नाम सामने आ सकता है।

क्या विभागीय मिलीभगत से चलता रहा खेल?

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किसी कर्मचारी के नाम पर आवंटित मकान पर वर्षों तक दूसरा व्यक्ति कैसे रहता रहा? यदि किराया वेतन से कट रहा था तो संबंधित शाखा, आवास विभाग और प्रबंधन ने कभी भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया? क्या यह केवल लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी विभागीय मिलीभगत छिपी हुई है?

कलेक्टर, एसपी और प्रशासन से लगाई गुहार

न्याय की आस में पुनियाबाई ने कलेक्टर शहडोल, पुलिस अधीक्षक शहडोल, तहसीलदार बुढार, थाना प्रभारी धनपुरी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी धनपुरी तथा एसईसीएल प्रबंधन को शिकायत देकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई, अवैध कब्जा हटाने तथा उन्हें उनके नाम से आवंटित आवास का वैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की है।

सबसे बड़ा सवाल

यदि एक महिला कर्मचारी के नाम पर 12 वर्षों तक किराया कटता रहा, लेकिन उसे अपने ही क्वार्टर की जानकारी नहीं थी, तो एसईसीएल की आवास व्यवस्था में और कितने ऐसे मामले दफन हैं? क्या जांच के बाद केवल कब्जाधारी पर कार्रवाई होगी या फिर उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिनकी निगरानी में यह पूरा खेल वर्षों तक चलता रहा? अब पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

1.20 अरब का बजट: फिर भी अस्तित्व के संकट से जूझ रहा धनपुरी

कोयले की नगरी में घट रही रौनक, रोजगार के अभाव में पलायन तेज; विकास के साथ आर्थिक पुनर्जीवन की उठी मांग

धनपुरी। कभी कोयला उत्पादन और आर्थिक समृद्धि के दम पर पूरे संभाग में अपनी अलग पहचान रखने वाला धनपुरी नगर आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां विकास के बड़े-बड़े दावों के बावजूद अस्तित्व का संकट गहराता दिखाई दे रहा है। नगर पालिका परिषद धनपुरी ने वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1 अरब 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है और नगर के विभिन्न वार्डों में विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन नगर के नागरिकों, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि केवल निर्माण कार्यों से धनपुरी का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा।

लोगों का कहना है कि वास्तविक विकास तब माना जाएगा जब नगर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार को नई ऊर्जा मिलेगी और वर्षों से कटे हुए क्षेत्रों को मुख्य नगर से जोड़ा जाएगा। अन्यथा अरबों रुपये खर्च होने के बाद भी धनपुरी की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आ सकेगा।

कभी 18 हजार कर्मचारियों से गुलजार था कोयलांचल

धनपुरी और सोहागपुर क्षेत्र का स्वर्णिम दौर वह था जब यहां संचालित लगभग 10 कोयला खदानों में करीब 18 हजार कर्मचारी कार्यरत थे। उस समय कोल कर्मियों की आय पर ही धनपुरी, बुढार और शहडोल के बड़े हिस्से का व्यापार निर्भर था। वेतन दिवस आते ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती थी और व्यापारियों के चेहरों पर अलग ही चमक दिखाई देती थी।

लेकिन वर्ष 1994 के बाद नियमित भर्ती प्रक्रिया लगभग बंद हो गई। लगातार सेवानिवृत्ति होती रही और कर्मचारियों की संख्या घटते-घटते लगभग 4 हजार तक पहुंच गई। परिणामस्वरूप बाजार की रौनक भी धीरे-धीरे खत्म होने लगी।

रोजगार के अभाव में खाली हो रहा नगर

धनपुरी के शिक्षित युवा रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। नगर में न तो कोई बड़ा

औद्योगिक निवेश हुआ और न ही ऐसी रोजगारपरक योजनाएं विकसित की गईं जो स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान कर सकें।

व्यापारियों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में धनपुरी की जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। कई परिवारों के युवा सदस्य पहले ही नगर छोड़ चुके हैं और शेष भी बेहतर अवसरों की तलाश में बाहर जाने को मजबूर हैं।

कटे हुए रास्तों ने तोड़ी विकास की कड़ी

नगर के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक वर्षों से बंद या उपेक्षित पड़े संपर्क मार्गों को माना जा रहा है। ओरिएंट पेपर मिल क्षेत्र, सरईकापा तथा आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्ग आज भी उपेक्षा का शिकार हैं।

स्थानीय नागरिकों का मानना है कि यदि नगर पालिका कार्यालय से बघइया पुल तक मॉडल रोड का निर्माण किया जाए तथा स्टेट हॉस्पिटल के समीप पुल बनाकर ओपीएम क्षेत्र को सीधे नगर से जोड़ा जाए तो व्यापार, आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है।

विकास के नाम पर खर्च हुए करोड़ों, लेकिन सवाल कायम

धनपुरी में वर्षों से विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन नगर की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकांश योजनाएं केवल निर्माण कार्यों तक सीमित रहीं, जबकि रोजगार, उद्योग और व्यापार विस्तार जैसे मूलभूत विषयों को प्राथमिकता नहीं दी गई।यही कारण है कि विकास के दावों के बावजूद नगर की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई।

कोयले के साथ उद्योगों की संभावनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि कोयला और ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध धनपुरी क्षेत्र में सहायक एवं लघु उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। यदि एसईसीएल प्रबंधन, जनप्रतिनिधि और प्रशासन समन्वित प्रयास करें तो यहां कोयला आधारित कई छोटे-बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और व्यापार को भी नई दिशा प्राप्त होगी।

बरसात से पहले वार्डों की समस्याएं बनी चुनौती

इधर मानसून की दस्तक के साथ नगर के विभिन्न वार्डों में पाइपलाइन विस्तार और अन्य निर्माण कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढे चिंता का विषय बने हुए हैं। कई स्थानों पर सड़कें जर्जर हैं और मरम्मत कार्य अधूरे पड़े हैं। बरसात शुरू होने के बाद यह स्थिति नागरिकों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका का पूरा ध्यान बड़े प्रोजेक्टों पर केंद्रित है, जबकि वार्ड स्तर की मूलभूत समस्याओं के समाधान में अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।

धनपुरी को चाहिए एक भागीरथ

स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक वर्ग का मानना है कि धनपुरी को ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है जो शासन, प्रशासन, एसईसीएल प्रबंधन, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय स्थापित कर सके। ऐसा नेतृत्व ही उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर रोजगार, उद्योग और व्यापार आधारित विकास की नई राह खोल सकता है।धनपुरी के पास आज भी संसाधनों की कमी नहीं है। आवश्यकता केवल ऐसी छोड और दूरगामी योजना की है जो विकास को केवल निर्माण कार्यों तक सीमित न रखकर आर्थिक समृद्धि और रोजगार से जोड़ सके। यदि समय रहते इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं हुए तो कोयले की यह नगरी आने वाले वर्षों में और बड़े आर्थिक संकट का सामना कर सकती है।

टीएमसी कंपनी पर श्रमिक शोषण के गंभीर आरोप

13 दिन की मजदूरी मांगने पर मिला जवाब

"जहां शिकायत करनी हो कर लो, पैसा नहीं मिलेगा"

ग्राम गोपालपुर क्षेत्र में संचालित टीएमसी कंपनी एक बार फिर श्रमिकों के भुगतान और कथित शोषण को लेकर विवादों के घेरे में आ गई है। कंपनी में ड्राइवर के पद पर कार्य कर चुके तीरथ सिंह अमलाई ने बुढ़ार थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके 13 दिनों के कार्य का भुगतान रोक रखा है और बार-बार मांग करने के बावजूद मजदूरी देने से साफ इनकार किया जा रहा है। आवेदन के अनुसार, तीरथ सिंह पहले टीएमसी कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन वेतन संबंधी विसंगतियों और असंतोषजनक परिस्थितियों के कारण उन्होंने नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में काम शुरू कर दिया। नौकरी छोड़ने के बाद जब उन्होंने अपने बकाया 13 दिनों के वेतन की मांग की, तो कंपनी प्रबंधन ने उन्हें लगातार टालना शुरू कर दिया।

तीरथ सिंह का आरोप है कि कई बार कंपनी कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी के एचआर विभाग तथा प्रोजेक्ट मैनेजर शिवम पांडे ने कथित तौर पर उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि, "तुम कंपनी छोड़ चुके हो, अब तुम्हारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। जहां शिकायत करनी हो कर लो, हम पैसा नहीं देंगे।"

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी श्रमिक ने निर्धारित अवधि तक कार्य किया है तो उसके श्रम का भुगतान रोकने का अधिकार किसी

कंपनी को कैसे मिल सकता है? श्रम कानूनों की खुली अवहेलना और मजदूरों के अधिकारों पर कथित कुठाराघात जैसे आरोप अब टीएमसी कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहे हैं।

स्थानीय श्रमिकों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी कंपनी पर समान कार्य के लिए अलग-अलग मजदूरी देने, भुगतान में भेदभाव करने तथा श्रमिकों के साथ मनमानी करने जैसे आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि कंपनी श्रम विभाग की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करने के बजाय अपनी सुविधानुसार वेतन संरचना लागू कर रही है। बिड़ला समूह से जुड़ी परियोजना में कार्यरत इस कंपनी पर लग रहे लगातार आरोप न केवल उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह की साख को भी प्रभावित कर रहे हैं। तीरथ सिंह ने प्रशासन से बकाया भुगतान दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर श्रमिकों के कथित शोषण पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। यदि समय रहते मामला नहीं सुलझा, तो श्रमिकों का आक्रोश बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। आप तो यह भी है की स्थानीय अनुभवि युवाओं को प्राथमिकता ना देकर अनट्रेंड श्रमिकों को कम पर रखा जा रहा है जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वही कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि टीएमसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मनमर्जी के हिसाब से यहां पर कर्मचारियों से काम लिया जाता है यदि कोई कर्मचारी इसका विरोध करता है तो उसे काम से पृथक कर दिया जाता है। ग्राम गोपालपुर में बिरला ग्रुप के अधीन कार्यरत दुर्ग रायपुर की कंपनी टीएमसी द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार न देकर बाहर के जिले के लोगों की भर्ती की गई है जबकि नियमानुसार कोई भी औद्योगिक संस्था किसी क्षेत्र में कार्य करती है तो नियमानुसार 70% स्थानीय योग्य बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के तौर पर कार्य पर रखना चाहिए लेकिन इसके विपरीत टीएमसी कंपनी द्वारा सीधी, अमरपाटन, रायगढ़, रायपुर मैहर, रीवा, सतना के लोगों को कर पर बड़ी संख्या में रखा गया है जिससे स्थानीय युवाओं की अपेक्षा की जा रही है कंपनी की तानाशाही के खिलाफ जल्द ही स्थानीय लोग जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे

साखी पंचायत के घटिया सडक की फोटो खीचने पर पत्रकार को मिली धमकी, तो संघ ने सौंपा ज्ञापन

ब्यौहारी। जनपद की बहुचर्चित ग्राम पंचायत साखी मे निर्माणाधीन एक पीसीसी सडक निर्माण कार्य की फोटो वीडियो बनाने पर दैनिक हरिभूमि के पत्रकार सूर्यभान यादव को अश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी मिली है मामले को लेकर पीडित ने थाना ब्यौहारी मे शिकायत देकर कार्यवाही की माग की है आवेदन दिऐ 3 दिन बीतने के बाद भी कार्य वाही नही होने पर आज मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के पत्रकार एकजुट होकर थाना पहुचे और थाना प्रभारी जियाउलहक से मिलकर ग्यापन सौप कार्यवाही की माग की है ! गौरतलब है कि ग्राम साखी मे वार्ड क्र01 मे सूसामटी के सामने से अंन्जनी बैस के घर तक एक पीसीसी सडक का निर्माण हो रहा है लोगो की शिकायत है कि उपरोक्त सडक मिट्टी की ढेर बिछाकर बनाई

जा रही है जिसमे वेस नही है स्टीमेड एवं ड्राइग डिजाइन के बिपरीत कराऐ जा रहे कार्य की स्थानीय पत्रकार द्वारा फोटो वीडियो बनाई जाकर समाचार प्रकाशित किया गया जिसे लेकर नीलेश सोनी द्वारा पत्रकार सूर्यभान यादव को फोन लगाकर मा बहन की जातिगतअश्लील गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी दी गई वो भी एक बार नही बल्कि बार बार, पीडित पत्रकार ने बताया कि नीलेश के बाद रामराज गुप्ता द्वारा भी हमे फोन किया जाकर अपमा नित किया गया मुझे भय है कि उपरोक्त लोग कभी भी कही भी हमारे साथ कुछ भी कर सकते है जिसके बाद आज आयोजित हुई संघ की बैठक मे घटना की निन्दा की गई और थाना प्रभारी को ग्यापन सौपा गया!

इन्होंने कहा:
आप लोग पावती ले लीजिये
हम कार्यवाही करेगे
जिया उल हक, नगर निरीक्षक
ब्यौहारी

एक छत के नीचे सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना शिविर का मुख्य उद्देश्य - कलेक्टर

जन कल्याण शिविर में एक ही स्थान पर मिली 111 प्रकार की योजनाओं की जानकारी

उमरिया। आमजन तक शासन की जनहितैषी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत मानपुर परिसर में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। कलेक्टर ने इस दौरान नगरीय स्तरीय षिविर का भी अवलोकन किया तथा प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण पूरी गंभीरता के साथ करने के निर्देष दिए। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जन कल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि शिविर में

हितग्राही अपनी समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका नियमानुसार परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने उपस्थित नागरिकों से समान नागरिक संहिता के संबंध में अपने सुझाव देने की अपील करते हुए कहा कि जनभागीदारी से ही बेहतर नीतियों का निर्माण संभव है। जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता सिंह ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा समय एवं संसाधनों की बचत होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविर का उद्देश्य आमजन को शासन की योजनाओं से जोडऩा और उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से 111 प्रकार की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी शिविर में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में 26 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी पंचायत में कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। वहीं, सीईओ जनपद पंचायत मानपुर ने जन कल्याण शिविर की रूपरेखा एवं विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। शिविर में कृषि, उद्यानिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय कार्य, वन, पशुपालन, आधार केंद्र तथा जल जीवन मिशन सहित विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक स्टॉल लगाए गए थे। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं अन्य अधिकारियों ने स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को विभिन्न प्रमाण पत्र एवं योजनाओं का लाभ वितरित किया गया। ग्राम जमुनारा निवासी लवकेश यादव को जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। जन कल्याण शिविर आमजन को शासन की योजनाओं से जोडऩे और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल साबित हुआ।

बावड़ी की सफाई कर जल संरक्षण का दिया गया संदेश

हरिभूमि न्यूज ⏭ स्लीमनाबाद

विकासखंड बहोरीबंद में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन अभियान परिषद द्वारा बावड़ी उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। जिला समन्वयक डॉ तेजसिंह केशवाल के मार्गदर्शन में ग्राम बाकल स्थित हनुमान मंदिर के पास स्थित बावड़ी की साफ-सफाई एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत एवं म.प्र. जन अभियान परिषद से संबद्ध नवांकुर संस्था आयुष जन कल्याण सेवा समिति पटना, मढ़िया ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, परामर्शदाता, सीएमसीएलडीपी छात्र छात्राओं, समाजसेवियों एवं ग्रामीणजनों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए बावड़ी की सफाई कर जल स्त्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया। ब्लॉक समन्वयक अरविंद शाह ने उपस्थित लोगों को वर्षाजल संचयन एवं जल संरक्षण की शपथ दिलाई।

खबर संक्षेप

कोयला भरे ट्रक मोड पर आमने-सामने टकराए, 4 घंटे तक आवागमन रहा प्रभावित

अनूपपुर। जिला मुख्यालय में मंगलवार को कृषि उपज मंडी मोड़ के समीप कोयला परिवहन कर रहे दो ट्रक आमने-सामने टकरा गए। जिससे सड़क पर लगभग 4 घंटे तक यातायात जाम की स्थिति बन गई। इसके बाद क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से किनारे किया गया तब जाकर के यातायात बहाल हो पाया। जानकारी अनुसार जिला मुख्यालय में चचाई मार्ग पर ट्रक क्रमांक सीजी एनएक्स 1419 जो की चचाई की तरफ से अनूपपुर की ओर आ रहा था वहीं सामने से कोयला भर कर ट्रक क्रमांक सीजी 10 बीआर 9890 अनूपपुर से चचाई रोड की ओर जा रहा था दोनों ही वाहन तेज रफ्तार में होने के कारण कृषि उपज मंडी मोड़ के पास अनियंत्रित होकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जिससे लगभग 4 घंटे तक मुख्य मार्ग पर दोनों वाहनों के खड़े होने से यातायात जाम की स्थिति निर्मित हो गई। सूचना मिलने के बाद यातायात और कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैकों को सड़क से हटाया गया। इस दौरान छोटे वाहन साइड से निकलते रहे लेकिन बड़े वाहन यातायात जाम में फंसे रहे।

चित्रकूट धाम से आए 72 वर्षीय संत शवासन मुद्रा में मड़फा तालाब सामतपुर में 2 घंटे पानी में करेंगे योग

अनूपपुर। योग साधक संत रामसखा पांडेय चित्रकूट धाम अनूपपुर स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी में रुके हुए हैं। जो कि आज प्रातः 11.00 बजे से शवासन मुद्रा में मड़फा तालाब सामतपुर में 2 घंटे पानी में योग करेंगे। जिसके लिए उन्होंने नगर पालिका, पुलिस अधीक्षक एवं कोतवाली को पत्र देकर जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर रेलवे कॉलोनी अनूपपुर के पुजारी ब्रह्मानंद गर्ग ने बताया कि संत जी उनके मंदिर पर रुके हुए हैं और आज वह 2 घंटे सामतपुर तालाब में पानी के ऊपर योग कर लोगों को योग की शिक्षा देंगे। योग साधक रामसखा पांडेय ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली में इंसान लगातार तनाव और बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे समय में योग ही एक ऐसा साधन है, जो तन-मन को संतुलित कर हर विपरीत परिस्थिति से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। योग साधक रामसखा पांडेय ने बताया कि वे देशभर में भ्रमण कर योग की शक्ति का संदेश दे रहे हैं। उनका मानना है योगाभ्यास से न केवल मानसिक शांति और शारीरिक मजबूती मिलती है, बल्कि तनाव और बीमारियों से भी बचाव होता है। उन्होंने कहा कि योग और आसन से हमेशा स्वस्थ रहा जा सकता है। जिन लोगों को हम स्वस्थ समझते हैं, वे भी पूर्णतः रोग मुक्त नहीं हैं। वे शारीरिक रूप से भले ही रोगी न हों, लेकिन मानसिक रूप से रोगी होते हैं। योग चिकित्सा का परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता है, लेकिन यह स्थाई रूप से लाभ पहुंचाता है। वर्तमान समय में लोग तनाव और बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में योग से तन और मन को संतुलित कर हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती है।

अवैध रेत परिवहन पर बिजुरी पुलिस की कार्रवाई

बिजुरी। बिजुरी पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 16 जून को गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से अवैध रेत परिवहन की सटीक सूचना मिली। बिजुरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धनिया ठेला तिराहा पर घेराबंदी की। इस दौरान बहेराबांध से बिजुरी की ओर आ रहे एक बिना नंबर के लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर को रोका गया। ट्रैक्टर चालक प्रमोद अगरिया उम्र 20 वर्ष पिता रमेश अगरिया, निवासी बहेराबांध से जब रेत के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज और रॉयल्टी रसीद मांगी गई, तो वह कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सका। चालक ने बहेराबांध से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर परिवहन करना स्वीकार किया, जिसके बाद गवाहों के समक्ष ट्रैक्टर मय रेत भरी ट्राली को जब्त कर लिया गया। जब्त ट्रैक्टर की कीमत 5,00,000 अवैध रेत (03 घन मीटर) की कीमत 5,000 कुल जब्त मशरुका 5,05,000 पुलिस ने आरोपी चालक के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस एवं 4/21 खनिज अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।

छील्पा की पीसीसी सड़क में भ्रष्टाचार के आरोप

पहली बारिश में बह जाएगा विकास?

अनूपपुर जिले की ग्राम पंचायत छील्पा में निर्माणाधीन पीसीसी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लगभग 4.63 लाख रुपये की लागत से बन रही सड़क में गुणवत्ता से समझौता, प्राक्कलन की अनदेखी और निर्माण के दौरान आवश्यक पानी की सिंचाई नहीं किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सड़क की सतह पर सीमेंट के बजाय गिट्टी दिखाई देने से ग्रामीणों को आशंका है कि पहली ही बारिश में सड़क उखड़ सकती है। मामला अब भ्रष्टाचार और जवाबदेही का मुद्दा बनता जा रहा है।

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

ग्राम पंचायत छील्पा में लक्ष्मण पटेल के घर से संतदास पटेल के घर तक लगभग 200 मीटर लंबी पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 144 22 मई 2026 तथा प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 21 24 मई 2026 के तहत 4 लाख 63 हजार रुपये की लागत से कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी द्वारा सड़क निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से लेकर पूर्णता तक सड़क की नियमित क्योरिंग (पानी की सिंचाई) नहीं कराई गई, जिसके कारण सड़क की ऊपरी सतह कमजोर दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में सीमेंट की मजबूती नजर नहीं आ रही और कई स्थानों पर गिट्टियां खुलकर दिखाई दे रही हैं। इससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और सड़क की तकनीकी जांच कराने की मांग की है।

सड़क बनी या भ्रष्टाचार का गलियारा?

ग्रामीणों का आरोप है कि जिस सड़क को वर्षों तक गांव की सुविधा का आधार बनना था, वह निर्माण के दौरान ही सवालों के घेरे में आ गई है। प्राक्कलन में निर्धारित मापदंडों और गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किए जाने से निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर संदेह गहराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य नियमानुसार हुआ होता तो सड़क की सतह इतनी जल्दी कमजोर नहीं दिखाई देती। इससे सरकारी धन के उपयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

क्योरिंग नहीं हुई, मजबूती पर उठे सवाल

पीसीसी सड़क निर्माण में पानी की नियमित सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के बाद एक भी दिन सड़क की क्योरिंग नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप सीमेंट पूरी तरह सेट नहीं हो पाया और सड़क की सतह पर गिट्टियां उभरकर दिखाई देने लगीं। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी स्थिति में सड़क की आयु प्रभावित हो सकती है। यदि आरोप सही हैं तो यह निर्माण गुणवत्ता में गंभीर लापरवाही का मामला माना जाएगा।

पंचायत और निर्माण एजेंसी की भूमिका पर प्रश्न

ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी और पंचायत के जिम्मेदार कर्मियों की मिलीभगत से कार्य कराया गया। उनका कहना है कि यदि निर्माण के दौरान नियमित निगरानी और तकनीकी परीक्षण किए जाते तो ऐसी शिकायतें सामने नहीं आतीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि कार्य के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियुक्त जिम्मेदार अधिकारियों ने निरीक्षण किया था या नहीं। यह मामला केवल एक सड़क का नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी बन गया है।

पहली बारिश बनेगी गुणवत्ता की असली परीक्षा

गांव के लोगों का कहना है कि सड़क की वास्तविक स्थिति पहली तेज बारिश के बाद सामने आ जाएगी। अभी से सतह पर दिखाई दे रही कमजोरियां इस आशंका को मजबूत कर रही हैं कि सड़क जल्द ही क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो लाखों रुपये की सार्वजनिक राशि व्यर्थ चली जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्यों का उद्देश्य जनता को सुविधा देना है, न कि कुछ समय बाद फिर से मरम्मत और नए निर्माण के नाम पर खर्च बढ़ाना।

जांच और कार्यवाही की उठी मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और तकनीकी विभाग से सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, सड़क की मोटाई, सीमेंट अनुपात और क्योरिंग प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाए। यदि अनियमितताएं सिद्ध होती हैं तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही ही ग्रामीणों का प्रशासन पर विश्वास कायम रख सकती है।

मॉनिटरिंग के लिए वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर दर्ज हो हर 15 दिन की प्रगति- कलेक्टर

कलेक्टर ने निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

अनूपपुर। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित नर्मदा सभागार में सोमवार को कलेक्टर हर्षल पंचोली ने विभिन्न निर्माण विभागों के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में शासकीय कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता, गतिशीलता और उच्च दक्षता लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए एकीकृत वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किया कि वे जिले के समस्त अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यों की जानकारी संबंधित विभागों से समन्वय कर इस पोर्टल पर हर 15 दिवस में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। पोर्टल पर कार्यों के करंट स्टेटस, वित्तीय व्यय, जमीन संबंधी विवाद, कमिटमेंट एंट्री के साथ समय और स्थान के स्टाम्प वाली लाइव फोटो अपलोड की जाएगी, ताकि विकास कार्यों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। कलेक्टर श्री पंचोली ने बैठक में शासन की योजना के अंतर्गत ग्रामों में संचालित निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। जिले की महत्वपूर्ण अधोसंरचना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अनूपपुर बायपास मार्ग हमारे जिले के प्रमुख विकास कार्यों में से एक है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी पूरी गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। कलेक्टर श्री पंचोली ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाले इस वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य लोक निर्माण विभाग (भवन), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, जनजातीय कार्य, जल संसाधन, सर्व शिक्षा अभियान, विद्युत तथा स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की परियोजनाओं को गति देना है। यह पोर्टल न केवल समय और वित्तीय संसाधनों की फिजूलखर्ची को रोकेगा, बल्कि पेपरलेस व्यवस्था के माध्यम से अंतर्विभागीय समन्वय को मजबूत कर जन-कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी प्रशासनिक देरी के समय पर पूरा करेगा। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गरिमामय लोकार्पण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएं। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी सहित विभिन्न निर्माण विभागों के कार्यपालन यंत्री व नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कैरत के काटने से बेटे की मौत के बाद मां भी हुई शिकार

जहरीले सांप के डंसने से नवविवाहिता की मौत

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

जिले में सर्पदंश की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उपचार के दौरान एक नवविवाहिता की मौत हो गई, जबकि करैत सर्प के काटने से युवक की मौत के दूसरे ही दिन उसकी मां को भी उसी प्रजाति के सांप ने डंस लिया। गंभीर हालत में महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है और चिकित्सकों ने उसे फिलहाल खतरे से बाहर बताया है।

दिशा मैदान जाते समय नवविवाहिता को सांप ने डसा

जानकारी के अनुसार शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र अंतर्गत सरईकापा गांव निवासी 24 वर्षीय सरिता चौधरी अपने मायके आई हुई थी। सोमवार देर रात भोजन के बाद वह घर के पीछे बाड़ी में गई थी, तभी

किसी अज्ञात जहरीले सांप ने उसकी जांघ के पास डंस लिया। सरिता के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और सांप की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल जिला चिकित्सालय अनूपपुर लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नवविवाहिता होने के कारण कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पंचनामा एवं अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

करैत सर्प के काटने से युवक की मौत

इधर भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के पयारी क्रमांक-1 निवासी 27 वर्षीय रविशंकर चौधरी को दो दिन पूर्व घर में जमीन पर सोते समय अत्यंत विषैले करैत सर्प ने काट लिया था। परिजन उसे तत्काल कोतमा अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया था।

बेटे के अंतिम संस्कार के बीच मां भी बनी सर्पदंश का शिकार

रविशंकर की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल था। अंतिम संस्कार और रिश्तेदारों के आने-जाने के बीच उसकी 48 वर्षीय मां इंद्रवती चौधरी घर में अन्य लोगों के साथ जमीन पर सो रही थीं। इसी दौरान देर रात करैत सर्प ने उनके हाथ की उंगली में डंस लिया। परिजनों ने सांप को मारकर महिला को पहले फुनगा अस्पताल और बाद में जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार समय पर उपचार मिलने से उनकी हालत में सुधार है और वे खतरे से बाहर हैं। बारिश के मौसम में सर्पदंश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, जमीन पर न सोने तथा सर्पदंश की स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचने की अपील की है।

प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन से आमजन को मिलेगा सुलभ प्रशासन-कलेक्टर

प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के संबंध में आयोजित हुई बैठक

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के द्वारा आईआईपीए की टीम लीडर प्रो. डॉक्टर नीतू जैन की उपस्थिति में आज मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग, भोपाल द्वारा नागरिकों की सुविधा, भौगोलिक परिस्थितियों और जन-अपेक्षाओं के अनुरूप एक सुलभ, पारदर्शी और जनोन्मुखी प्रशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वपुर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ाना और आम जनता को उनके नजदीक ही बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की मुख्य प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिले के संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड जैसी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन तथा युक्तियुक्तकरण की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लीडर प्रोफेसर डॉ. नीतू जैन ने कहा कि शासन की मंशा जनता को त्वरित प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि यह आयोग नागरिकों की व्यावहारिक सुविधाओं और स्थानीय जन-अपेक्षाओं का बारीकी से अध्ययन कर अपनी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं शासन को सौंपेगा। प्रशासनिक सीमाओं के इस पुनर्गठन से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों के लिए भी शासकीय कार्य बेहद आसान हो जाएंगे। इस महत्वपूर्ण विमर्श के दौरान उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से मैदानी स्तर पर कार्य निष्पादन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और भौगोलिक विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री पंचोली ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जमीनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने व्यावहारिक सुझाव आयोग के समक्ष रखें। आयोग की टीम ने इन सभी बिंदुओं को गंभीरता से नोट करते हुए आगामी रूपरेखा में शामिल करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अर्चना कुमारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.के. सोनी, डिप्टी कलेक्टर कमलेश पुरी, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार सहित विभिन्न निर्माण व प्रशासनिक विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे, जिन्होंने इस पुनर्गठन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय चरण का भव्य शुभारंभ, शिक्षा के प्रति किया जागरूक

अनूपपुर। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित स्कूल चले हम अभियान-2026 के द्वितीय चरण के अंतर्गत शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बस्ती, अनूपपुर में मंगलवार को उत्साह एवं उल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सहभागिता रही। अभियान के तहत विद्यालय द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने लोगों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने तथा नियमित रूप से स्कूल भेजने का संदेश दिया। रैली के माध्यम से यह भी अपील की गई कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और प्रत्येक बालक-बालिका को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार प्रसाद ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों का नियमित रूप से विद्यालय आना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई एवं गृहकार्य पर विशेष ध्यान देने तथा किसी भी शैक्षणिक कठिनाई की स्थिति में शिक्षकों से संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालय से जोड़ने के लिए भी समाज से सहयोग की अपेक्षा की। कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका सविता प्रजापति द्वारा नवप्रवेशी एवं उपस्थित विद्यार्थियों का तिलक एवं पुष्प से स्वागत किया गया। वहीं प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को विशेष भोजन और मिष्ठान स्वरूप जलेबी वितरित की गई। बच्चों को नियमित उपस्थिति बनाए रखने एवं शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए भविष्य में प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद श्रीमती कंचन गजेंद्र

अमरकंटक मंडलम कांग्रेस की वार्ड कमेटी बैठक संपन्न संगठन विस्तार एवं जनहित के मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा

हरिभूमि न्यूज, अमरकंटक। नगर परिषद अमरकंटक क्षेत्र में मंडलम कांग्रेस द्वारा वार्ड कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाने, आगामी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कांग्रेस संगठन की मजबूती एवं कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण रणनीतियां निर्धारित की गईं। बैठक को संबोधित करते हुए पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक फुन्देलाल सिंह मार्को ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते और उनके समाधान के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रत्येक वार्ड एवं बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी विचारधारा तथा संगठनात्मक गतिविधियों को घर-घर तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने का माध्यम बनता है। बैठक में पुष्पराजगढ़ विधानसभा प्रभारी पंडित जानकी मिश्र ने संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल देते हुए कार्यकर्ताओं को वार्ड स्तर पर नियमित जनसंपर्क अभियान चलाने की सलाह दी। वहीं आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को ने आदिवासी समाज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर पूर्व जनपद उपाध्यक्ष संतोष कुमार पांडेय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की एकजुटता, अनुशासन और निरंतर जनसंपर्क पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने, वार्ड कमेटियों को सक्रिय करने तथा जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान तथा बूथ स्तर पर कांग्रेस को और अधिक मजबूत बनाने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं वार्ड प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने संगठन को नई ऊर्जा एवं मजबूती प्रदान करने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।

न्यायालयः - सुश्री सुधा पाण्डेय
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
क्रमांक-02/न्याया./2026
अनूपपुर, दिनांक 11.06.2026
जयराम यादव बनाम सेंट्रल बैंक
MJCSUC-21/2025
पेशी दिनांक- 25.07.2026
आवेदक/वादी जयराम यादव, आशाराम यादव, अकलिया यादव बहिन चंदा बाई यादव व अनावेदक क्रमांक 02 भाई जगतराम यादव द्वारा अपनी बड़ी मां दुअसिया बाई है, जो लावल्द फौत है, जिनके विधिक वारिस आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 02 है। मृतक दुअसिया बाई का सेंट्रल बैंक शाखा जैतहरी में बचत खाता क्रमांक 2193316600 संधारित है जिसमें लगभग 11,00,000/- रुपए (ग्यारह लाख रुपए मात्र) जमा है जिसे प्राप्त करने हेतु विधिक वारिस आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 02 है जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किये है। जिसकी सुनवाई दिनांक 25.07.2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण आवेदकगण को उक्त मृतक दुअसिया बाई का आवेदकगण उत्तराधिकारी होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनाक 25.07.2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की कार्यवाही एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण कर दिया जावेगा।
यह आज तारीख 11.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(सील)
सुश्री सुधा पाण्डेय
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
अनूपपुर, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर (म.प्र.)
अनूपपुर, दिनांक 01 जून 2026
अधिसूचना
एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डायरेक्टर, जय अम्बे रोडलाईस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर (छ.ग.) द्वारा एसईसीएल को आवंटित ग्राम खांडा तहसील व जिला अनूपपुर (म. प्र.) स्थित आराजी खसरा नम्बर 336/15, 336/2/35, 336/2/25, 240/85, 240/55, 240/45 पर स्वयं के उपयोग हेतु 100 किलोलीटर डीजल भण्डारण हेतु कन्ज्यूमर्स पंप स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। अतः पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम, 144 के अन्तर्गत, प्रस्नगत आराजी पर डीजल पम्प की स्थापना से यदि किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति अधिसूचना प्रकाशित होने के 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत कर सकता है । निर्धारित अवधि समाप्त होने उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
(सील)
डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, अनूपपुर (म.प्र.)

नायब तहसीलदार
वृत अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़
जिला अनूपपुर म. प्र.
रा.प्र.क्र.0001/अ-20(2)/
2026-27/टी.प्रो.क्र.0147
दिनांक - 15/6/2026
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड जबलपुर. द्वारा ग्राम अमरकंटक पटवारी हल्का अमरकंटक तहसील पुष्पराज जिला अनूपपुर (म. प्र.) की शासकीय/ नजूल भूमि खसरा न. 196/4 रकवा 405 से अंश रकवा 100X100 वर्ग फीट भूमि पेट्रोल पम्प संचालन प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन के लिए न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला अनूपपुर (म.प्र.) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो आगामी कार्यवाही हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। उक्त आवंटन में जिस किसी को आपत्ति हो वह इश्तहार जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर अपनी आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में उपस्थित हो कर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नही किया जाएगा।
आज दिनांक 15/6/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।
(सील)
नायब तहसीलदार
वृत अमरकंटक,
तहसील पुष्पराजगढ़